

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 434

06 फरवरी, 2019 को उत्तर के लिए

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तारण

434. श्री राम विचार नेताम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र सहित सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्यक्रम (एमईपी) आरंभ किया गया है/आरंभ किए जाने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आधुनिकीकरण की अनुमानित लागत एवं आवंटित धनराशि संयंत्र-वार कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की सभी इस्पात कंपनियों को उनके एमईपी के तहत ऊर्जा दक्षता एवं उत्सर्जन की कमी संबंधी प्रावधान करने का निर्देश दिया है; और
- (घ) ऐसे प्रत्येक संयंत्र के आधुनिकीकरण के कार्य को आरंभ और पूरा करने की संभावित तिथि क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त संयंत्रों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आधुनिकीकरण करने तथा राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को कार्यान्वित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय व्यक्तिगत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार गतिशीलता के आधार पर लिया जाता है। दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने अपने इस्पात संयंत्रों में आधुनिकीकरण और विस्तारण का कार्य हाल ही में शुरू किया है। इसमें भिलाई (छत्तीसगढ़), बोकारो (झारखंड), राउरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बर्नपुर (पश्चिम बंगाल), सेलम (तमिलनाडु) में स्थित सेल के इस्पात संयंत्र और विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में स्थित आरआईएनएल के इस्पात संयंत्र शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए वित्त-पोषण, संबंधित कंपनी द्वारा स्वयं के संसाधनों से और/या बैंक/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण से किया जाता है।

सेल के संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सांकेतिक निवेश 61,870 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, खानों के विकास और विस्तार के लिए 10,264 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आरआईएनएल की कुल सांकेतिक लागत 16,291 करोड़ रुपये है। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना का संयंत्र-वार ब्यौरा निम्नवत् है:-

संयंत्र	कूड इस्पात क्षमता एमटीपीए में (मिलियन टन प्रतिवर्ष)		अनुमोदित लागत करोड़ रुपये में (नेट सेनवेट)
	विस्तार पूर्व	विस्तार के पश्चात्	
सेल			
भिलाई इस्पात संयंत्र	3.93	7.0	17,266
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1.8	2.2	2,875
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1.9	4.2	11,812
बोकारो इस्पात संयंत्र	4.36	4.61	6,325
इस्को इस्पात संयंत्र	0.5	2.5	16,408
सेलम इस्पात संयंत्र	-	0.18	1,902
विभिन्न संयंत्रों में रख-रखाव योजना	-	-	5,282
आरआईएनएल			
विजाग इस्पात संयंत्र	3.0 (तरल इस्पात क्षमता)	6.3 (तरल इस्पात क्षमता)	12,291
विजाग इस्पात संयंत्र	6.3 (तरल इस्पात क्षमता)	7.3 (तरल इस्पात क्षमता)	4,000

(ग) देश में इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार कार्यक्रम इकाइयों को ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने की परिकल्पना से किया जाता है। किसी भी इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार परियोजना के लिए, सरकार के संबंधित एजेंसियों/विभागों से पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त की जाती है। ऊर्जा-दक्षता और उत्सर्जन में कमी का प्रावधान पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया में अंतर्निहित है।

(घ): सेलम स्थित सेल के इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तारण का कार्य सितंबर, 2010 में, दुर्गापुर का जून, 2015 और बोकारो का सितंबर, 2015 में पूरा किया गया। आधुनिकीकृत और विस्तारित राउरकेला इस्पात संयंत्र, इस्को इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र को दिनांक 01.04.2015, 10.05.2015 और 14.06.2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।

आरआईएनएल ने अप्रैल, 2015 में विजाग इस्पात संयंत्र की तरल इस्पात क्षमता को 3 एमटीपीए से 6.3 एमटीपीए तक दोगुना करने के लिए विस्तारण कार्य पूरा कर लिया है। आरआईएनएल ने तरल इस्पात क्षमता को 1 एमटीपीए अर्थात् 6.3 एमटीपीए से 7.3 एमटीपीए तक बढ़ाने के लिए, एक और कन्वर्टर और कास्टर को संस्थापित किया। सभी आधुनिकीकृत और पुनर्निर्मित इकाइयाँ तथा अतिरिक्त कन्वर्टर और कास्टर इकाइयाँ प्रचालन में हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियाँ वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार गतिशीलता के आधार पर नियमित रूप से अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा परियोजनाओं में समय-समय पर पूँजीगत निवेश करती हैं।
